INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

BPSC

बिहार लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

भाग – 4

भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**BPSC (Bihar Public Service Commission) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

Whatsapp करें - https://wa.link/gubxrj

Online Order करें - https://bit.ly/42ANSs2

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

भारत की अर्थव्यवस्था

1.	अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय • अर्थव्यवस्था के प्रकार • अर्थव्यवस्था के फायदे व नुकसान • अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	1
2.	भारतीय बजट • बजट निर्माण • बजट के प्रकार • बजट निर्माणकारी एजेंसियाँ • रेल बजट v/s आम बजट • बजट 2023-24	6
3.	लोक वित्त • लोक वित्त का महत्त्व • राजकोषीय उत्तरदायित्व बिल प्रबंधन एक्ट-2003 • वस्तु एवं सेवा कर (GST)	19
4.	संवृद्धि एवं विकास • आर्थिक संवृद्धि	29
5.	राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ • राजकोषीय नीति की परिभाषा • मौद्रिक नीति की परिभाषा	31

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

6.	सब्सिडी एवं लोक वितरण प्रणाली • सब्सिडी के प्रकार • सब्सिडी के फायदे • सब्सिडी के नुकसान • सार्वजनिक वितरण प्रणाली • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएँ	35
7.	मुद्रास्फीति की अवधारणा • मुद्रास्फीति के प्रकार • मुद्रा स्फीति के प्रभाव एवं नियंत्रित करने के उपाय • मांग और पूर्ति प्रबंधन	45
8.	केंद्र- राज्य वित्तीय संबंध • जीएसटी से प्रभावित संवैधानिक अनुच्छेद-	58
9.	भारतीय कृषि क्षेत्र • कृषि के अन्य प्रकार एवं प्रतिरूप • प्रमुख फसलें • हरित क्रान्तिः- • सिंचाई • जल संसाधन • राष्ट्रीय जल नीतियाँ • खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एवं खाद्य प्रबंधनः • कृषिगत सुधार • भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ	63

10.	औद्योगिक क्षेत्र • औद्योगिक नीति का महत्त्व • भारत में औद्योगिक नीति का विकास • औद्योगिक वित्त • प्रमुख उद्योग- • उदारीकरण, निजीकरण ,वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार • अवसरंचना एवं आर्थिक वृद्धि	89
11.	आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका • नीति आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम	112
12.	आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहलें • पंचवर्षीय योजना	117
13.	मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास • मानव विकास सूचकांक • वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022	124
14.	गरीबी, बेरोजगारी एवं नई शिक्षा नीति	128
15.	केंद्र सरकार की योजनाएँ	146

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.	वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष • विश्व बैंक संगठन और कार्य • विश्व व्यापार संगठन • यूरोपीय संघ • भारत और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन	151
2.	सतत् विकास एवं जलवायु परिवर्तन	161

बिहार की अर्थव्यवस्था

1.	अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	165
2.	राजकीय वित्तव्यवस्था	171
3.	कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	175
4.	उद्यम क्षेत्र	185
5.	श्रम, रोजगार तथा कौशल	192
6.	भौतिक अधिसंरचना	198
7.	ई-शासन	202
8.	ऊर्जा क्षेत्र	216
9.	ग्रामीण विकास	220

10.	नगर विकास	226
11.	बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र	230
12.	मानव विकास	235
13.	बाल विकास	253
14.	पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन	262

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अर्थशास्त्र

अध्याय – I

अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय

परिचयः-

- Economics (अर्थशास्त्र) शब्द एक Greek word ' Oikonomia ' से उत्पन्न हुआ है ।
- Oikonomia शब्द Oikos and Nomos दो शब्दों से मिलकर बना है ।
- Oikos का अर्थ गृह अथवा परिवार जबकि Nomos का का अर्थ है प्रबंधन । अर्थात् Oikonomia गृह प्रबंधन की प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है ।

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतरः-

अर्थशास्त्र	अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है	अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
अर्थशास्त्र केवल अध्ययन का क्षेत्र है	अर्थव्यवस्था निष्पादन (Execution) की भूमिका निभाती है।
अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है इनकी किताब (The Wealth of nations) मे अर्थव्यवस्था का विस्तार किया है।	जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं ।
अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं- (i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics) (ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)	अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
	अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यावहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था इत्यादि ।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economic)

- अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(i) व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)
(ii) समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

अर्थव्यवस्था के प्रकारः-

A. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy):-

- जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है उसे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
- अर्थात् यहाँ आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है।
- एडम स्मिथ की 'दा वेल्थ ऑफ़ नेशन' पूँजीवाद को दार्शनिक आधार प्रदान करता है।
- अमेरिका समेत पश्चिमी यूरोपीय देश पूँजीवाद के समर्थक हैं।

पूँजीवाद के फायदे या गुणः-

- पूँजीवाद नवाचार को बढ़ावा देता है।
- पूँजीवाद और समाज दोनों स्वतंत्रता और अवसर पर केंद्रित हैं।
- पूँजीवाद आबादी की जरूरतों को पूरा करता है।
- पूँजीवाद स्व-नियामक है।
- पूँजीवाद समग्र रूप से समाजों की मदद करता है।

पूँजीवाद के नुकसान या दोषः-

- धन और आय के वितरण की असमानता
- पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य के रूप में कक्षा संघर्ष
- सामाजिक लागत बहुत अधिक है
- पूँजी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता
- बेरोजगारी और रोजगार के तहत

- वर्किंग क्लास में पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं है ।

B. समाजवाद अर्थव्यवस्था

- उत्पादन एवं वितरण के सामूहिक नियंत्रण पर बल देता है।
- राज्य द्वारा विनियमित निजी क्षेत्र की भूमिका से लोक कल्याण के उद्देश्य की प्राप्ति।
- भारत,बांग्लादेश,ब्राजील,समेत विकासशील अधिकांश देश समाजवाद के समर्थक हैं।
- बौद्ध और जैन धर्म का अस्तेय आवश्यकता से अधिक संसाधनों के एकत्रीकरण का विरोध करता है, जो समाजवाद की अवधारणा के अनुकूल है।
- अशोक के शिलालेखो से लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती हैं, वहीं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में प्रमाण देता है।
- इसी प्रकार मध्यकाल में फिरोजशाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण, बेरोजगारों के लिए पेंशन जैसी समाजवादी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है।

समाजवाद के पक्ष में तर्क या गुण:-

शोषण का अन्त:-

- समाजवाद श्रमिको एवं निर्धनो के शोषण का विरोध करता है। इसलिये विश्व के श्रमिक किसान निर्धन इसका समर्थन करते है।

सामाजिक न्याय पर आधारित:-

- समाजवादी व्यवस्था में किसी वर्ग विशेष के हितो को महत्व न देकर समाज के सभी व्यक्तियों के हितो को महत्व दिया जाता है यह व्यवस्था पूँजीपतियों के अन्याय को समाप्त करके एक ऐसे वर्गविहीन समाज की स्थापना करने का समर्थन करती है जिसमें विषमता न्यनूतम हो।

उत्पादन का लक्ष्य सामाजिक आवश्यक्ता:-

- व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था में समाजिक आवश्यक्ता और हित को ध्यान में रखकर उत्पादन होगा क्योंकिसमाजवाद इस बात पर बल देता है कि जो उत्पादन हो वह समाज के बहुसख्यक लोगो के लाभ के लिए हो।

उत्पादन पर समाज का नियंत्रण :-

- समाजवादियो का मत है कि उत्पादन और वितरण के साधनो पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करके विषमता को समाप्त किया जा सकता है।
- सभी को उन्नति के समान अवसर
- साम्राज्यवाद का विरोधी

समाजवाद के विपक्ष में तर्क अथवा आलोचना :-

राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि :-

- समाजवाद मे आर्थिक तथा राजनीतिक दोनो क्षेत्रों में राज्य का अधिकार होने से राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा किये जाने वाले कार्य समुचित रूप से संचालित और समपादित नहीं होंगे।

वस्तुओं के उत्पादन में कमी :-

- समाजवाद के आलोचको की मान्यता है कि यदि उत्पादन के साधनो पर सम्पूर्ण समाज का नियंत्रण हो तो व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी और कार्यक्षमता भी धीरे धीरे घट जायेगी।
- व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा तो वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा घट जायेगी।

समाजवाद प्रजातंत्र का विरोधी :-

- प्रजातंत्र में व्यक्ति के अस्तित्व को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है वही समाजवाद में वह राज्य रूपी विशाल मशीन में एक निर्जीव पूर्जा बन जाता है।

नौकरशाही का महत्व :-

- समाजवाद में राज्य के कार्यो में वृध्दि होने के कारण नौकरशाही का महत्व बढ़ता है। और सभी निर्णय सरकारी कर्मचारियो द्वारा लिये जाते है ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता है।

समाजवाद हिंसा को बढ़ाता है :-

- समाजवाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी तथा हिंसात्मक मार्ग को अपनाता है। वह शांतिपूर्ण तरीको में विश्वास नहीं करता।
- वह वर्ग संघर्ष पर बल देता है। जिसके परिणामस्वरूप समाज में वैमनस्यता और विभाजन की भावना फैलती है।
- पूर्ण समानता संभव नहीं ।

C. मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) :-

- यहाँ, उत्पादन की कुछ योजनाएँ राज्य द्वारा सीधे या इसके राष्ट्रीयकृत उद्योगों के माध्यम से शुरू की जाती है, और कुछ को निजी उद्यम के लिए छोड़ दिया जाता है।
- इसका अर्थ है कि समाजवादी क्षेत्र (यानी सार्वजनिक क्षेत्र) और पूँजीवादी क्षेत्र (यानी निजी क्षेत्र) दोनों एक-दूसरे के साथ हैऔर एक-दूसरे के पूरक हैं।
- इसे बाजार की अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच आधे घर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थान आर्थिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। इसलिए, इस प्रकार कीअर्थव्यवस्था पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदेः-

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन :-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करता है और इसे बढ़ने का उचित अवसर मिलता है।
- यह देश के भीतर पूँजी निर्माण में वृद्धि की ओर जाता है।

स्वतंत्रताः-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक और व्यावसायिक दोनों तरह की स्वतंत्रता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है।
- इसी तरह, हर निर्माता उत्पादन और खपत के संबंध में निर्णय ले सकता है।

संसाधनों का इष्टतम उपयोगः-

- इस प्रणाली के तहत, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए काम करते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक लाभ के लिए काम करता है जबकि निजी क्षेत्र लाभ के अधिकतम करण के लिए इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है।

आर्थिक योजना के लाभः-

- मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आर्थिक योजना के सभी फायदे हैं।
- सरकार आर्थिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने और अन्य आर्थिक बुराइयों को पूरा करने के लिए उपाय करती है।

कम आर्थिक असमानताएँः-

- पूँजीवाद आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है लेकिन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत, सरकार के प्रयासों से असमानताओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रतियोगिता और कुशल उत्पादनः-

- निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण दक्षता का स्तर उच्च बना हुआ है।
- उत्पादन के सभी कारक लाभ की उम्मीद में कुशलता से काम करते हैं।

सामाजिक कल्याणः-

- इस प्रणाली के तहत, प्रभावी आर्थिक, योजना के माध्यम से सामाजिक कल्याण को मुख्य प्राथमिकता दी जाती है।
- सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को नियंत्रित किया जाता है।
- निजी क्षेत्र की उत्पादन और मूल्य नीतियां अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के लिए निर्धारित की जाती हैं।

आर्थिक विकासः-

- इस प्रणाली के तहत, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना के विकास के लिए अपने हाथ मिलाते हैं, इसके अलावा, सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कई विधायी उपाय लागू करती है।
- इसलिए, किसी भी अविकसित देश के लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था सही विकल्प है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के नुकसानः-

स्थिरताः-

- कुछ अर्थशास्त्रियों का दावा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अस्थिर है।
- सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकतम लाभ मिलता है जबकि निजी क्षेत्र नियंत्रित रहता है।

क्षेत्रों की अक्षमताः-

- इस प्रणाली के तहत, दोनों क्षेत्र अप्रभावी हैं।
- निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती है, इसलिए यह अप्रभावी हो जाता है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र में अप्रभाविता की ओर जाता है।

अध्याय - 2

भारतीय बजट

बजट निर्माण

- बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को कहा जाता हैं।
- लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, वित्तीय व्यवस्था। शासन द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती हैं। यह धन कहाँ से आयेगा? और यह धन कहाँ-कहाँ खर्च होगा? यह सभी बातें सुविचारित तथा सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इसी व्यवस्था को बजट के नाम से जाना जाता हैं।

बजट का अर्थ

- स्पष्ट है कि शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को बजट कहा जाता हैं। यह लेखा एक वर्ष का हो सकता है या उससे अधिक वर्ष का भी हो सकता हैं। इस लेखे में वर्ष में विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का वर्णन रहता है, साथ ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी रहता है कि उसके लिए जरूरी धन कहाँ से आयेगा? नये करों का प्रावधान भी उसमें रहता हैं।

एक अच्छे बजट के मुख्य लक्षण या विशेषताएं

1 बजट एक निश्चित अवधि के लिए आय-व्यय का अनुमान है।

2 यह एक तुलनात्मक तालिका भी है, जिसमे प्राप्तियों व खर्चों की राशियों की तुलनात्मक विवेचना होती हैं।

3 यह सरकार के लिये धन उगाही और व्यय के लिये विधायिका का आदेश हैं।

4 यह प्रशासन के कार्यों का वित्तीय प्रतिवेदन हैं।

बजट के प्रकार (Types Of Budget)

(1) निर्माण के आधार पर (On the Basis of Construction):

i व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित बजट ।

ii कार्यपालिका द्वारा निर्मित बजट (भारत में यही प्रचलित हैं) ।

iii मण्डल या आयोग द्वारा निर्मित बजट (अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित हैं) ।

(2) स्वरूप के आधार पर (On the Basis of Format):

(A) लाइन आइटम बजट (Line-Item Budget):

यह बजट का परम्परागत रूप है । यह 18वीं-19वीं सदी में विकसित हुआ । इस बजट में वस्तुओं या मद का महत्व अधिक होता है । उन मदों या वस्तुओं पर खर्च से क्या उद्देश्य हासिल होगा, इस पर नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य अपव्यय, अधिक खर्च और बर्बादी को रोकना है ।

i. लाइन-आइटम बजटिंग में सार्वजनिक व्यय पर कठोर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य को प्रमुखता दी जाती है । इसमें बजट को सार्वजनिक खर्च पर नियन्त्रण रखने की विधि के रूप में देखा जाता है जिसका परिणाम वस्तुनिष्ठ बजट के रूप में सामने आता है ।

ii. इसमें व्यय की प्रत्येक मद को पंक्तिवार (लाइन) लिखा जाता हैं ।

iii. इसमें यह देखा जाता है कि जिस मद पर खर्च की स्वीकृति हुई है, वह उसी पर व्यय हो, यद्यपि लाइन आइटम बजट को इस वस्तुनिष्ठता के बजाय एक दूसरे रूप में भी बनाया जाता है । जिसमें एक मद का पैसा दूसरे मद में भी खर्च करने की अनुमति रहती हैं।

iv. इसमें खर्च की जाने वाली राशि पर जोर अधिक रहता है, उससे क्या परिणाम हासिल हुआ, उस पर नहीं ।

v. इसे अभिवर्धन बजट व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि बजट राशि सदैव पूर्व की अपेक्षा अधिक दी जाती है । वैसे यही बजट अन्य सुधारात्मक बजट जैसे शून्य बजट आदि का आधार होता हैं।

(B) कार्य निष्पादन बजट (Performance Budgeting):

- यह वर्ष 1930 की मंदी का परिणाम था ।
- सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुवर आयोग (1949) ने इसकी सिफारिश की थी और 1950 में राष्ट्रपति ट्रुमेन ने इसे अपनाया था ।
- निष्पादन बजट (Performance Budget) शब्दावली सर्वप्रथम हुवर कमीशन (1949) ने ही प्रयुक्त की थी ।

- 2003 में कैबिनेट सचिव के आदेशानुसार प्रत्येक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विभाग को यह निर्देश दिया गया कि अपने वार्षिक रिपोर्ट में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को एक भिन्न खंड के अंतर्गत प्रकाशित करें वर्ष 2004 में वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया कि सभी मंत्रालयों में जनवरी , 2005 तक एक जेंडर बजटिंग सेल होना चाहिए । यह जेंडर बजटिंग सेल उन कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु जिम्मेदार होता है जो 100 % महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है । साथ ही यह उन कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु भी जिम्मेदार होता है , जिनके कम से कम 30 % प्रावधान महिला उत्थान के लिए हों । अत : जेंडर बजटिंग देश में सामाजिक न्याय की स्थापना का एक उपकरण बन गया है ।

- **रेल बजट एवं आम बजट का विलय**

- वर्ष 1924 से पूर्व रेल बजट एवं आम बजट दोनों साथ प्रस्तुत किए जाते थे ।
- हालांकि इस आम बजट में रेलवे की हिस्सेदारी अर्थव्यवस्था के अन्य आयामों की प्राप्तियों एवं व्यय से कहीं ज्यादा हुआ करती थी । इस दौरान रेलवे का बजट में व्यापक योगदान सरकार की कमियों को उजागर होने से रोकता था ।
- अतः पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे आयोग का गठन किया गया ।
- 1920 में गठित इस आयोग की संस्तुति के आधार पर 1924 में आम बजट एवं रेल बजट को पृथक् कर दिया गया आजादी के बाद स्थिति की पुन : समीक्षा की गई ।
- आम बजट एवं रेल बजट को अलग - अलग प्रस्तुत करने की यह प्रक्रिया 92 वर्षों तक जारी रही और अंततः बजट 2017-18 में इन दोनों का विलय कर दिया गया ।

बजट 2023-24

2023-24 का बजट अनुमान

- कुल प्राप्तियां (उधारी के अलावा)- 27.2 लाख करोड़
- कुल व्यय - 45 लाख करोड़
- नेट टैक्स प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़

बजट 2023 की खास बातें

- भारत की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर 1.97 रु. हुई।
- अगले एक साल तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी।
- पीएम सुरक्षा के तहत् 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा।
- बागवानी योजनाओं पर रहेगा जोर, 2200 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान।
- कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड रुपए किया जाएगा।
- 157 नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग हिस्सों में खोले जाएंगे।
- अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ खर्च होंगे।
- पीएम आवास योजना फंड में 66 फ़ीसदी की बढ़ोतरी।

बजट 2023 में क्या हुआ सस्ता और महंगा?

- सस्ता - इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, साइकिल, लिथियम बैटरी, हीरे के आभूषण।
- महंगा:- सोना, आयातित चाँदी, प्लेटिनम, विदेशी किचन चिमनी, सिगरेट।

Note:- 2023-24 का बजट अमृत काल में पहला बजट है।

- बजट: व्यय, कर, लेन- देन और योजनाओं का ब्लूप्रिंट है।
- संविधान के अनुच्छेद- 112 में बजट शब्द का उपयोग न करते हुए इसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है।
- यह बजट आगामी वर्ष 2023- 24 के लिए पेश किया गया है।
- वर्ष 2022- 23 में भारत की विकास दर 7% के आस-पास रही है, जो दूसरे देशों की तुलना में

बहुत बेहतर है, क्योंकि ऐसी महामारी कोविड-19 और वैश्विक मंदी जो रही है।

- वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रतिशत रखा गया था। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में काफी हद तक सफल रही है।
- वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.9 प्रतिशत रखा गया है और इसे 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य है ।
- वर्ष 2023-24 का बजट 7 मूल आधारों पर आधारित है, जिसे सप्त ऋषि- 7 कहा गया है।

1. समावेशी विकास - (a)कृषि (b)स्वास्थ्य क्षेत्र (c)शिक्षा क्षेत्र
2. वित्तीय क्षेत्र
3. युवा शक्ति
4. आखिरी व्यक्ति तक पहुंच
5. अवसंरचना निवेश
6. सक्षमता का विकास
7. हरित विकास

कृषि और सहकारिता:- ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि
उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम
भारत को श्री अन्न देने के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारत बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य।
भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग।
भारत मिलेट (बाजरा) को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है।

स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि:- वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 प्रतिशत।

- वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए उन्मूलन मिशन की शुरुआत।
- चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सीय अनुसंधान को प्रोत्साहन।
- फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत।
- आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना : "कोई पीछे न छूटे"
- प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की शुरुआत।
- कर्नाटक के सूखा संभाव्य क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता।
- 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती।
- PMGKAY के तहत्, सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को एक वर्ष के लिए **मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।**
- प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए 'भारत श्री' योजना की शुरुआत।
- पीएम- आवास योजना के परिव्यय में 66% की वृद्धि।
- अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश :-
- विकास व रोजगार के अवसरों में वृद्धि:
- पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट, अवसंरचना में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हित धारकों की सहायता करेगा।
- UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी- 2 और श्रेणी- 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन।
- राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा।

Note- अमृत काल के लिए संकल्पना: "सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था"
इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

1. नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना।
2. विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना।
3. वृहद् आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना।

अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं -

1. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:
2. पीएम- विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)
3. पर्यटन
4. हरित विकास

अध्यापकों का प्रशिक्षण:- नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत् पेशेवर विकास, डिपास्तिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा।

- बच्चों और किशोरों के लिए **"राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय"** की स्थापना की जाएगी।

❖ **अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना**: -सरकार द्वारा आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया गया है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1
(C) केवल 2 और 3
(D) 1 , 2 , 3 और 4 **(A)**

2. संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन – सा/ से गैर – योजना व्यय के अधीन आता है / आते हैं ?
1. रक्षा व्यय
2. ब्याज अदायगी
3. वेतन एव पेंशन
4. उपदान
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये :
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) 1 2 3 और 4
(D) कोई नहीं **(C)**

3. भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिये संसाधनों को बढ़ाने के लिये उपयोग की जाती है ?
(A) आर्थिक विकास के लिये
(B) सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिये
(C) भुगतान शेष का समायोजन करने के लिये
(D) विदेशी ऋण कम करने के लिये **(A)**

4. निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है ?
(A) लोक ऋण की चुकती ।
(B) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये जनता से ऋणादान ।
(C) बजट घाटे के वित्तीयन के लिये बैंकों से ऋणादान ।
(D) बजट घाटे के सृजन के लिये नई मुद्रा **(D)**

5. निम्नलिखित में से कौन - सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम , 2003 में अनुबद्ध नहीं है ?
(A) राजकोषीय वर्ष 2007-08 की समाप्ति तक राजस्व घाटे को खत्म करना ।
(B) केंद्र सरकार द्वारा RBI से कतिपय परिस्थितियों के सिवाय उधार न लेना ।
(C) राजकोषीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना ।
(D) सरकारी गारंटियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की प्रतिशतता के रूप में नियत करना । **(C)**

• वस्तु एवं सेवा कर
GOODS & SERVICES TAX

वस्तु एवं सेवा कर GOODS & SERVICE TAX [GST]
GST की नीव आज से 16 वर्ष पहले रखी गयी थी, इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन भारत सरकार ने 2010 से GST लागू करने का प्रस्ताव रखा था तथा मार्च 2011 में लोकसभा में इसे पेश किया गया। दिसम्बर 2014 में एक बार फिर से GST विधेयक संसद में पेश किया गया तथा मई 2015 में इसे लोकसभा में पारित किया गया । राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद यह संविधान का 122 वां संशोधन कहलाया । पूरे भारत देश में इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा रहा है।
25 साल पहले अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद GST के रूप में अप्रत्यक्ष करों में क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में GST मील का पत्थर साबित होगा।

क्या है GST:
GST अर्थात वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Service Tax) एक अप्रत्यक्ष (Indirect) कर (Tax) है। यह एक एकीकृत कर (Integrated Tax) है जो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लगेगा।
GST लागू होने के बाद पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जायेगा और अधिकतर अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty), सेवा कर (Service Tax)वैट VAT (Value Added Tax), मनोरंजन कर आदि सभी अप्रत्यक्ष कर समाप्त होकर GST में समाहित हो जायेंगे ।
इसके बाद भारत एक सिंगल टैक्स वाली अर्थव्यवस्था बन जायेगा अर्थात देश में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग-अलग टैक्स खत्म हो जायेंगे ।और फिर नये आंकड़े के अनुसार देश के सभी लोग सेवाओं एवं वस्तुओं पर केवल एक ही Tax देंगे जिसे GST के नाम से जाना जायेगा।
दुनिया के करीब 165 देशो में GST लागू है न्यूजीलैंड में 15% ऑस्ट्रेलिया में 10% फ्रान्स में 19.6% जर्मनी में 19%तथा पाकिस्तान में 18%की दर सेGST लागू है ।
GST से पहले भारत के Tax System में सबसे बड़ा सुधार वर्ष 2005 में किया गया था । तब Tax को

VAT अर्थात् मूल्य निर्धारित कर जो कि एक बाजार कर होता है,में बदल दिया गया था। इसकी मदद से अलग-अलग चरणों में लगने वाले करों को कम करने की कोशिश की गयी थी

लेकिन VAT भी "टैक्स पर टैक्स" लगने वाली व्यवस्था का अंत नहीं कर पाया | VAT उन वस्तुओं पर भी लगता है जिनके लिये Excise Duty चूका दी गयी हो यानि लोगो को Tax पर भी अलग से Tax देना पड़ता था|

भारत में Tax की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं की मैन्युफैकचुरिंग (Manu Facturing) पर Excise Duty देनी पड़ती है और जब ये वस्तुएं बिक्री पर लायी जाती है तो इस पर Sales Tax और Vat (VAT) अतिरिक्त लग जाता है ।

इसी तरह उपलब्ध करायी गयी सेवाओं पर लोगों से Service Tax वसूला जाता है लेकिन GST लागू होने के बाद इन करों का बोझ समाप्त हो जायेगा।

GST के प्रकार:

- केंद्र वसूलेगा (CGST)
- राज्य वसूलेगा (SGST)
- एक साथ दोनों वसूलेंगे (IGST)

संघीय ढांचे को बनाये रखने के लिये GST तीन स्तरों पर लगेगा। :-

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)-

इस कर को केन्द्र सरकार वसूलेगी।

राज्यवस्तु एवं सेवा कर (SGST)- इस कर को राज्य सरकारे वसूलेगी।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) - एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्तिथि में यह कर लगेगा।

IGSTका एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा।

क्यों आवश्यक है GST

भारत का वर्तमान कर ढांचा (Tax Structure) बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रुप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार तथा वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के अधीन है।

इस कारण देश में अलग-अलग प्रकार के कर लागू है जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल हो गयी है । कंपनियो व छोटे उद्योगों के लिये इन विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इन सभी जटिलताओं को खत्म करने के लिये ही GST को लागू किया जा रहा है।

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)- वह कर जिसे आपसेसीधे तौर पर वसूला जाता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है।

उदाहरण- कृषि कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर,निगम कर आदि |

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) – जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाये अर्थात वास्तविक भार उस व्यक्ति को नहीं देना पड़ता जो उस अदा करता है |

उदाहरण – Excise Tax (उत्पापन कर), सीमा शुल्क(Custom Tax) सेवाकर (Service Tax),VAT (बाजार कर) आदि|

उदाहरण- माना कोई वस्तु 100 रुपये में तैयार हुयी है और उस वस्तु पर Tax लगा 12%जिससे उस वस्तु की कीमत होगयी 112 रुपये। चूंकि उस वस्तु के निर्माण में लागत आयी 8 रुपये, तो उस वस्तु की कुल कीमत हो गयी 120 रुपये |

माना अब 120 रुपये वाली वस्तु पर 18%टैक्स लगना था लेकिन यहां पर उस वस्तु को कच्चे माल के रुप में पहले ही खरीदा जा चुका है तथा उस पर 12% टैक्स भी पहले ही लग चुका है अतः इस बात पर 18% टैक्स नही लगेगा। 18% से 12% घटाकर मात्र6% टैक्स ही लगेगा, जिससे वस्तुओं की कीमतों में पहले की अपेक्षा स्थिरता आयेगी।

यही है GSTका सबसे बड़ा फायदा जो टैक्स पर टैक्स लगाने वाली प्रथा को खत्म करेगा|

आइये अब इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते है |

इस चार्ट के माध्यम से समझे-

	वर्तमान स्थिति में वस्तु की कीमत	GST लागू के बाद पड़ने वाला प्रभाव

पहला चरण (निर्माता)	एक उधमी100 रुपये का कपड़ा खरीदता है। इसमें 10 रुपये का अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है। इससे तैयार शर्ट कि लागत आयी30 रुपये। शर्ट तैयार होने पर कीमत रखी गयी 130 रुपये इस पर लगता है 10% टैक्स (कर) 130 रु. इज 10% से कुल कर हुआ 13 रुपये शर्ट कि कुल कीमत 130 + 13 = 143 रुपये	· एक उधमी 100 रुपये का कपडा खरीदता है। · इससे 10 रुपये का अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है। · इससे तैयार शर्ट कि लागत आती है 30 रुपये । · शर्ट तैयार होने पर वह कीमत रखता है 130 रुपये। · इस पर लगता है 10% कर । · 130 रुपये पर 10% से कुल कर हुआ 130 रुपये । · इस पर लगता है 10% कर । · 130 रुपये पर 10% से कुल कर हुआ 130 रुपये । · क्योंकि वह 10 रुपये का टैक्स कपड़ा खरीदते वक्त दे चुका है अतः उसे कर देना होगा 13-10=3 रुपये।
दूसरा चरण (थोक विक्रेता)	· थोक विक्रेता ने इसे 143 रुपये में खरीदा · 20 रुपये का मुनाफा जोड़ने पर कीमत 163 रुपये । · 10% का कर लगने के बाद कीमत 16.30 रुपये · कर जोड़ने का शर्ट की कुल कीमत हो गयी 179.30 रुपये ।	· थोक विक्रेता ने इसे 130 रुपये में खरीदा । · 20रुपये का मुनाफा जोड़ने पर शर्ट की कीमत 150 रुपये । · 10% का टैक्स लगने बाद कीमत 15 रुपये । · निर्माता इस पर पहले ही 13 रुपये कर का भुगतान कर चुका है । अतः थोक विक्रेता को पहले छूट मिलेगी , कर के रूप में उसे अदा करना होगा 15-13=2 रुपए GST
तीसरा चरण रिटेलर (खुदरा व्यापारी)	· थोक विक्रेता ने रिटेलर को शर्ट 179.30 रुपये में · रिटेलर ने पैंकिंग कर के 10 रुपये का मुनाफा जोड़ा शर्ट की कीमत हो गयी 189.30 रुपये · इस पर लगता है 10% का टैक्स अतः 189.30 रुपये पर देना होगा 18.9 रुपये टैक्स	· थोक विक्रेता ने रिटेलर को 150 रुपये में शर्ट बेची। · रिटेलर ने इसकी पैंकिंग करके 10 रुपये का मुनाफा जोड़ा , शर्ट कि कीमत हो गयी 160 रुपये। · थोक विक्रेता के स्तर तक 15 रुपये का भुगतान पहले ही हो चुका है अतः रिटेलर को देने होगें 16-15= केवल 1 रुपया ।
कुल कीमत	अतः शर्ट पर निर्माता, थोक विक्रेता और रिटेलर के स्तर पर लगा कुल वर्तमान करो का मूल्य, 10+13+16.3+18.9=58.23 रुपये टैक्स शर्ट की कुल कीमत होगी – 143+58.23=201.23 रुपये	अतः शर्ट पर निर्माता, थोक विक्रेता और रिटेलर के स्तर पर लगा कुल वर्तमान करों का मूल्य, 10+3+2+1= केवल 16 रुपये GST शर्ट की कीमत होगी 130+16=146 रुपये

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index- MPI): बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 (MPI)

- आरंभ- 2010 से
- संस्थाएं - संयुक्त सहयोगी संस्था राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
- आधार - स्वास्थ्य , शिक्षा व जीवन स्तर (3 आधार)
- मानक – 10
- इसके आधार पर भारत का स्थान 62वाँ (out of 107)
- भारत - MPI = 0123
- भारत में गरीबी -27.91 %

राष्ट्रीय बहु - आयामी गरीबी सूचकांक 2021(NMPI)

- जारी कर्ता- नीति आयोग
- इसके आधार पर भारत का स्थान 66वाँ (out of 109)
- भारत में गरीबी – 25%
- आधार- Nation Family Health Survey -4 (वर्ष 2015-16)
- सर्वाधिक गरीबी - बिहार
- न्यूनतम गरीबी – केरल

अध्याय – 14
गरीबी, बेरोजगारी एवं नई शिक्षा नीति

- **बेरोजगारी (Unemployment)**
- बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हैं।
- या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है।
- बेरोजगारी को समझने के लिए श्रम बल और कार्य बल के बीच अन्तर समझना अति आवश्यक है।
- **श्रम बल**- देश में 15 वर्ष की आयु लेकर 60 वर्ष की आयु तक के लोग श्रम बल के अंतर्गत आते हैं।
- **कार्य बल** - श्रम बल लोग जिनको कार्य/रोजगार मिल जाता है राष्ट्र का कार्य बल कहलाते हैं।
- अतः बेरोजगारी को निम्न रूप में भी समझा जा सकता है।
  बेरोजगारी = श्रमबल - कार्यबल
- जब किसी देश में पूर्ण श्रम बल को रोजगार प्राप्त हो जाए अर्थात पूर्ण श्रम बल, कार्य बल में बदल जाये तब देश में पूर्ण रोजगार होगा।
  पूर्ण रोजगार = श्रमबल = कार्यबल

बेरोजगारी का मापन (Measurement of Unemployment)

- बेरोजगारी को मापने के लिए वर्ष 1970 में भगवती समिति बनायी गयी थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर बेरोजगारी को मापने के लिए तीन तरीके बनाये गये।

दीर्घकालिक बेरोजगारी

- यदि किसी सर्वेक्षण वर्ष में किसी व्यक्ति को 183 दिन (8 घंटे प्रति दिन) रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता हैं। वर्तमान में इस 183 दिन के मानक को बदल कर 273 दिन कर दिया गया है।

साप्ताहिक बेरोजगारी

- यदि किसी व्यक्ति को सप्ताह में 1 दिन (8 घंटे) का काम न मिले तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

दैनिक बेरोजगारी

- यदि किसी को प्रति दिन आधे दिन (4 घंटे) का काम न मिले तो उसे दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

भारत में बेरोजगारी (unemployment in India)

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)	शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)
1. अदृश्य बेरोजगारी (Disguised Unemployment) 2. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)	1. औद्योगिक बेरोजगारी (industrial Unemployment) 2. शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)

शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment)

- औद्योगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment): औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप के अन्तर्गत कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं परन्तु बेरोजगार हैं।
- देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि के कारणों में औद्योगीकरण की धीमी प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग शामिल है।

शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment):

पढ़े-लिखे लोगों द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। भारत में शिक्षित वर्ग में रोजगारी की समस्या अत्यधिक गंभीर है। इसका मुख्य कारण है।

- देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे- विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना ।
- भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगारपरक नहीं बल्कि उपाधिपरक है अर्थात् भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है।

ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment)

प्रच्छन / अदृश्य बेरोजगारी (Disguised unemployment) : जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं जबकि उतने लोगों की जरूरत नहीं होती है, तो यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है।

- इसमें सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है।
- यह जनसंख्या के अधिक दवाव और रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहती है।
- इसे पूंजी निर्माण, गैर-कृषि गतिविधियों के विकास के द्वारा किया जाता है इस बेरोजगारी का माप संभव नहीं है।

मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) :

एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम में कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाती है।

बेरोजगारी के अन्य प्रकार (Other types of unemployment)

पूर्ण बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी

- यदि किसी व्यक्ति के पास 35 कार्य दिवस से भी कम दिनों का रोजगार हो तो वार्षिक स्तर पर उसे पूर्ण बेरोजगार माना जाता है।
- यदि उसके कार्य दिवस 35 से ज्यादा एवं 135 दिनों से कम हो तो उसे अर्द्ध बेरोजगार माना जायेगा।
- 135 दिनों से अधिक के रोजगार की स्थिति में उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है।

संरचनात्मक बेरोजगारी (Structured Unemployment)

- यह एक दीर्घकालीन समस्या है। यदि देश की उत्पादक संस्थाओं की संख्या में कमी, तकनीकी परिवर्तन आदि के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं तो श्रमशक्ति का एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में पायी जाती है।
- यह आपूर्ति पक्ष में कमी एवं विसंगति के कारण उत्पन्न होता है।

है। इन दोनों में विपरीत सम्बंध Inverse Relation) पाया जाता है।

- ओकुन के नियमानुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी।
- इसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है तो उस देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 3% की कमी होगी

भारत में रोजगार की स्थिति

भारत में बेरोजगारी की स्थिति :- जनवरी - मार्च 2022 में यह 10.1 % थी, पुरुषों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर - अप्रैल - जून 2022 में घटकर 7.1 % हो गई जो एक साल पहले 12.2% थी। जनवरी - मार्च 2022 में यह 7.7% थी।

भारत में बेरोजगारी के आकड़े

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट – 2022 (CMIE- 2022)

- भारत- 7.8%
- प्रथम स्थान – हरियाणा (34.5%)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 (PLFS-2020-21)

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) द्वारा अप्रैल, 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत की।
- **बेरोजगारी दर:** इससे पता चलता है कि बेरोजगारी दर वर्ष 2020-21 में गिरकर 4.2% हो गई, जबकि वर्ष 2019-20 में यह दर 4.8% थी। क्षेत्रों में 3.3% तथा शहरी क्षेत्रों में 6.7% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई।

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

- जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात् काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिये उपलब्ध) में व्यक्तियों का प्रतिशत पिछले वर्ष के 40.1% से बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान 41.6% हो गया।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):

यह पिछले वर्ष के 38.2% से बढ़कर 39.8% हो गया।

- **प्रवासन दर: -**प्रवासन दर 28.9% है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रवास दर क्रमशः 48% और 47.8%थी।

रोजगार का वर्गीकरण

- NSSO सर्वेक्षण पूरी आबादी को तीन कैटेगरियों में विभाजित करता है।
- कैटेगरी 1 में उन लोगों को रखा गया है, जो सर्वे अवधि के दौरान आर्थिक गतिविधियों (Work) में शामिल थे।
- इस श्रेणी में शामिल लोगों को कार्यरत (Employed) कहा जाता है। साथ ही इस कैटगरी को तीन भागों में बांटा गया है- स्वरोजगार (Self-employed), वेतनभागी कर्मचारी (Salaried employees) और सामान्य मजदूरों (Casual labourers)
- कैटेगरी 2 में उन लोगों को शामिल किया गया है, जो किसी भी प्रकार के आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके पास काम होने के बाद भी वे काम की तलाश में थे। ऐसे लोगों को 'बेरोजगार' की श्रेणी में रखा गया है।
- कैटगरी 1 और 2 में शामिल लोग ही श्रम शक्ति का हिस्सा है।
- कैटेगरी 3 में उन लोगों को शामिल किया गया है, जो न तो काम में लगे हुए हैं और न ही इसके लिए उपलब्ध है।
- इस कैटगरी में लोगों को "श्रम शक्ति में नहीं शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में बड़ी संख्या में उन लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले, पढ़ाई करने वाले, विकलांगता के कारण काम करने में असमर्थ लोग और "केवल" घरेलू कर्त्तव्यों का हिस्सा है।
- यह नई स्टडी 'रोजगार के स्तर पर फोकस करते है जो कैटेगरी 1 है।

स्टडी की मुख्य बातें

- स्टडी में पाया गया कि ईयूएस 2004-05 और पीएलएफएस 2017-18 के बीच 13 वर्षों में देश कुल रोजगार 5 करोड़ बढ़ा है।
- यह सिर्फ 8 प्रतिशत की वृद्धि है- जिस पर कुल जनसंख्या में वृद्धि दर आधी से भी कम थी, जो 1.7 प्रतिशत थी।

शहरी-ग्रामीण में रोजगार की स्थिति

रोजगार में 4.5 करोड़ की वृद्धि में से 4.2 करोड़ शहरी क्षेत्रों में है, जबकि 2011 और 2017 के बीच ग्रामीण रोजगार या तो अनुबंधित या स्थिर रहा।

पुरुष महिला रोजगार की स्थिति

- पिछले 13 सालों में पुरुष रोजगार में 6 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन महिला रोजगार में 5 करोड़ की गिरावट आई।
- दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो जब 2004 में 15 करोड़ महिलाएँ नौकरी करती थीं, तो 13 साल बाद केवल 9.67 करोड़ महिलाएँ ही रोजगार कर पाने में सक्षम हैं।
- 2004 में महिलाओं की हिस्सेदारी 8% थी, जो 2017 में घटकर अब 21.17 प्रतिशत हो गई।

युवा रोजगार

- भारत दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रों में से एक है, लेकिन आयु समूहों के अनुसार रोजगार के आँकड़ों से पता चलता है कि युवा रोजगार (15 से 24 साल के बीच के) 2004 में 14 करोड़ से गिरकर 2017 में 5.34 करोड़ हो गए हैं।
- हालांकि, 25-59 आयु वर्ग और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में रोजगार बढ़ गया है।
- निरंतर स्कूली शिक्षा सुधारों ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर अपना प्रभाव 2004 में 61 लाख से घटाकर 2011 में 27 लाख, और 2017 में सिर्फ 11 लाख में दिखाया।

शिक्षा स्तर पर रोजगार

- उभरती अर्थव्यवस्था निरक्षरों और अधूरी प्राथमिक शिक्षा वाले लोगों को पीछे छोड़ती हुई प्रतीत होता है।
- इस श्रेणी में रोजगार 2004 में 20.08 करोड़ से घटकर 2017 में 14.2 करोड़ हो गया, और नियोजित लोगों में उनका हिस्सा 2004 में 48.77 प्रतिशत से घटकर 2017 में 31.09 प्रतिशत हो गया।
- प्राइमरी, सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और उससे ऊपर तक की अन्य सभी श्रेणियों के लिए रोजगार बढ़ गया है।

संगठित क्षेत्र

- संगठित क्षेत्र उन फर्मों का प्रतिनिधित्व करता है जो नियामक प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत हैं और विभिन्न श्रम कानूनों द्वारा बाध्य हैं।
- यहाँ रोजगार वृद्धि की दर सबसे तेज रही है, और कुल नियोजित में इसकी हिस्सेदारी 2004 में 9 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 14 प्रतिशत हो गई है।
- वास्तव में, जबकि इसकी विकास दर धीमी रही है, अर्थव्यवस्था में इसकी समग्र हिस्सेदारी 2004 में 37.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 47.7 प्रतिशत हो गई है।
- हालांकि, 2011 के बाद से असंगठित क्षेत्र के विकास की गति में कमी आई है।
- इन दोनों क्षेत्रों में कृषि फसल क्षेत्र की कीमत पर वृद्धि हुई है, जहाँ रोजगार 2004 में 9 प्रतिशत से गिरकर 2017 में 17.4 प्रतिशत हो गया है।
- संक्षेप में, परिणाम बताते हैं कि जो लोग गरीब, निरक्षर और अकुशल हैं वे तेजी से नौकरियाँ खो रहे हैं।

बेरोज़गारी से निपटने हेतु सरकार की पहलः

भारत में बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए सभी सरकारों द्वारा इससे निपटने के कई प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों में कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है

- "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE)
- पीएम-दक्ष (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- केन्द्र सरकार ने उद्योगों की माँग के अनुरूप श्रम बल को विकसित करने के लिए सन् 2015 में स्किल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की।
- केन्द्र सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिये 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए क्रेडिट या ऋण सीमा की व्यवस्था की गई है।
- केन्द्र सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
- देश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु 'स्टैण्डअप तथा स्टार्ट अप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गयी है।
- केन्द्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया है जिसके

बिहार की अर्थव्यवस्था

अध्याय- I

अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

बिहार की अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में अच्छी वापसी की। त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2020-21 के (-) 3.2 प्रतिशत की तुलना में 10.98 प्रतिशत की जबर्दस्त वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68 प्रतिशत थी।

- बिहार देश का अपेक्षाकृत कम आय वाला राज्य है। त्वरित अनुमान के अनुसार, 2021-22 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,75,448 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रु. था।
- 2021-22 में राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 6,14,431 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रु. था।
- फलतः बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 54,383 रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 34,465 रु. था।
- प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करने वाले दो उप-क्षेत्र 'पशुधन' और 'मत्स्याखेट एवं जलकृषि' हैं जिनकी वृद्धि दरें 2017-18 और 2021-22 के बीच क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत रही हैं।
- हालांकि 'खनन एवं उत्खनन' क्षेत्र में भी 90 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं (ईजीडब्ल्यूयूएस) में 2017-18 और 2021-22 के बीच 14.5 प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई।
- 2017-18 और 2021-22 के बीच तृतीयक क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र वायु परिवहन (10.5 प्रतिशत), भंडारण (21.3 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं (12.6 प्रतिशत) और लोक प्रशासन (9.3 प्रतिशत) थे।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रमुख क्षेत्रों के हिस्से के लिहाज से देखें, तो 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2020-21 के 21.4 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 21.2 प्रतिशत रह गया।
- द्वितीयक क्षेत्र में भी थोड़ी गिरावट आई जो 2020-21 के 19.3 प्रतिशत से 2021-22 में 18.1 प्रतिशत रह गया।
- वहीं, 2020-21 और 2021-22 के बीच तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 59.3 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 38 जिलों की रैंकिंग में तीन सबसे समृद्ध जिले पटना (1,15,239 रु.), बेगूसराय (45,497 रु.) और मुंगेर (42,793 रु.) हैं।
- दूसरी ओर, तीन सबसे गरीब जिले शिवहर (18,692 रु.), अररिया (19,527 रु.) और सीतामढ़ी (20,631 रु.) हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि

बिहार के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य, दोनो लिहाज से सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद दोनो के लिए तैयार किए जाते हैं। गत पांच वर्षों (2017-22) में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। कोविड-19 के कारण 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 3.2 प्रतिशत कमी आ गई। वर्ष 2021-22 में देश के शक्ति प्राप्त कार्य समूह (ईएजी) के राज्यों के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद की सर्वाधिक 11.0 प्रतिशत वृद्धि दरें राजस्थान और बिहार की थीं जबकि सबसे कम 4.2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की थी।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद और शक्ति-प्राप्त कार्य समूह के राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दरें

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2017-18 से 2021-22)
बिहार	**7.9**	**10.9**	**4.4**	**-3.2**	**11.0**	**4.6**
छत्तीसगढ़	3.0	8.0	5.1	-1.8	अनु.	3.8
झारखंड	9.0	8.9	1.1	-5.5	8.2	1.9
मध्य प्रदेश	5.6	9.3	5.9	-1.9	10.1	5.0
ओडिशा	7.0	7.1	2.9	-4.2	10.2	2.9
राजस्थान	5.2	2.4	5.7	-2.9	11.0	3.4
उत्तर प्रदेश	4.4	3.9	3.9	-5.5	4.2	1.0
उत्तराखंड	7.9	2.8	0.6	-4.4	6.1	3.1
भारत	**6.8**	**6.5**	**3.7**	**-6.6**	**8.7**	**2.0**

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मध्यकालिक वृद्धि दरें (2017-18 से 2021-22)

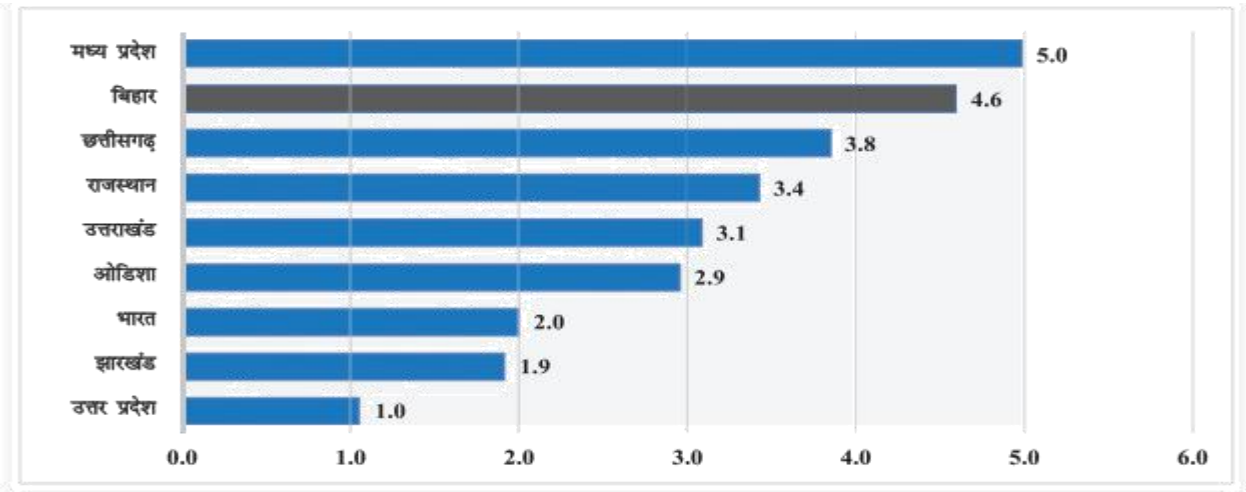

त्वरित अनुमान के अनुसार, 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के 587.15 हजार करोड़ रु. की तुलना में 675.45 हजार करोड़ रु. था। इसका अर्थ 15.0 प्रतिशत की

वृद्धि है जबकि 2020-21 में वृद्धि मात्र 0.8 प्रतिशत थी।

वहीं, 2021-22 में वर्तमान मूल्य बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 54,383 रु. था जो 2020-21 के 47,983 रु. 13.3 प्रतिशत अधिक था।

बिहार का राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

	राज्य घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रु.)			वृद्धि दर	
	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	398.28	385.73	428.06	-3.2	11.0
(ii) वर्तमान मूल्य पर	582.52	587.15	675.45	0.8	15.0
प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	33036	31522	34465	-4.6	9.3
(ii) वर्तमान मूल्य पर	48318	47983	54383	-0.7	13.3
निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	359.20	344.18	382.27	-4.2	11.1
(ii) वर्तमान मूल्य पर	533.23	533.58	614.43	0.1	15.2
प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)					
(i) 2011-12 के स्थिर मूल्य पर	29794	28127	30779	-5.6	9.4
(ii) वर्तमान मूल्य पर	44230	43605	49470	-1.4	13.5

टिप्पणी : 2020-21 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2021-22 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।
स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 428.06 हजार करोड़ रु. तक पहुंच जाने की संभावना है जो 2020-21 के 385.73 हजार करोड़ रु. से 11.0 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019-20 से 2020-21 के बीच वृद्धि दर निश्चित रूप से ऋणात्मक (-3.2 प्रतिशत) थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में स्थिर मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 8.7 प्रतिशत बढ़ा ।

वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 382.27 हजार करोड़ रु. था, जिसके आधार पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 30,779 रु. होता है। वहीं, वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में अनुमानित निवल राज्य घरेलू उत्पाद 614.43 हजार करोड़ रु. है, जिससे प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 49,470 रु. होता है।

राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत के विभिन्न राज्यों के लिए 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान नियमित रूप से प्रकाशित करता है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जबकि इस अवधि में संपूर्ण भारत के लिए वृद्धि दर मात्र 0.1 प्रतिशत थी।

वर्ष 2021-22 में राज्य का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 के 28,127 रु. से 9.4 प्रतिशत बढ़कर 30,779 रु. हो गया । वर्ष 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (28,127 रु.) राष्ट्रीय औसत (85,110 रु.) का मात्र 33.1 प्रतिशत था । यह अनुपात 2021-22 में बढ़कर 33.7 प्रतिशत हो गया है

लेकिन बिहार को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक दर पर बिजली मिलती है। राज्य सरकार के कार्यक्रम

विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि) :- राज्य सरकार की विशेष शेजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा किया गया। यह योजना विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए बनाई गई थी।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

केंद्र सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की शुरुआत की है। वितरण कंपनियों की संचालन कुशलता में सुधार और वित्तीय सुस्थिरता के लिए यह सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

(क) वित्तीय रूप से टिकाऊ और संचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र के जरिए उपभोक्ताओं को होने वाली बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और किफायतीपन में सुधार लाना,

(ख) वर्ष 2024-25 तक संपूर्ण भारत में सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक (एटी एंड सी) ह्रास को घटाकर 12 से 15 प्रतिशत के स्तर पर लाना, और

(ग) औसत आपूर्ति व्यय (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच फासले को 2024-25 तक घटाकर शून्य कर देना।

इस योजना के तहत कार्यों के ये लक्ष्य हैं -

(क) कृषि फीडरों का निर्माण,

(ख) लंबे फीडरों को बांटना,

(ग) निम्न विभव वाली लाइनों के वेयर कंडक्टरों की जगह एरियल बंच्ड केवल लगाना,

(घ) उच्च विभव वितरण प्रणाली (एचवीडीएस),

(च) सूचना प्रौद्योगिकी / संचालन प्रौद्योगिकी (आइटी / ओटी) और शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना।

अध्याय - 9

ग्रामीण विकास

जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (बीआरएलपीएस) ने राज्य में 1.27 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर खुद को राज्यव्यापी आंदोलन में तब्दील कर दिया है। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 स्वयं सहायता समूह बने थे जिनमें से 2.45 लाख का बैंकों के साथ ऋण - संपर्क हो चुका था। अभी उनका कुल बकाया ऋण 5574 करोड़ रु. है।

- मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 2021-22 में 48.0 लाख हो गई। रोजगार सृजन भी काफी बढ़ा और 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख व्यक्ति दिवस पहुंच गया। मनरेगा के तहत खुले खातों की कुल संख्या 2017-18 में 67.0 लाख थी जो 2021-22 में बढ़कर 104.9 लाख हो गई।
- मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्यों में लगातार वृद्धि हुई है जो 2017-18 के महज 1.1 लाख से 2021-22 में 13.0 लाख हो गई। इसी प्रकार योजना के तहत धनराशि का उपयोग भी बढ़ा और 2017-18 के 91.2 प्रतिशत से 2021-22 में 98.1 प्रतिशत हो गया।
- बासगीत जमीन के वितरण के लिए कुल बजट आवंटन 2019-20 के 4057.00 करोड़ रु. से बढ़कर 2021-22 में 7148.99 करोड़ रु. हो गया। योजना के विभिन्न घटकों के तहत कुल 84,494 पात्र परिवारों को बासगीत जमीन उपलब्ध कराई है। शेष 27,356 परिवारों को 2022-23 तक बासगीत जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी।
- जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आबंटन हुआ जिसमें से 2208.2 टन गेहूं और 3266.7 टन चावल था। वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच खाद्यान्नों का औसत उठाव 97.9 प्रतिशत था। आंकड़े दर्शाते हैं कि सभी जिलों में गेहूं और चावल का उठाव लगभग 100 प्रतिशत था।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के क्रियान्वयन के लिए 4290 पंचायतों को चुना गया है और 99.5 प्रतिशत पूर्णता दर के साथ 57,690 वार्डो में काम पूरे हो गए हैं। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली

नाली पक्कीकरण योजना के तहत कुल 8386 पंचायत चुने गए जिनमें 1,14,691 वार्ड हैं। संशोधित लक्ष्य वाले सभी वार्डों में से 1,14,507 में काम पूरे हो गए हैं।

- सात निश्चय -2 के तहत, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे।
- साथ ही विद्यालय, पुस्तकालय आदि सामुदायिक संस्थानों के लिए हर पंचायत में 10 अतिरिक्त सोलर स्ट्रीट लाइट होगी। यह देश में अपने किस्म की पहली योजना है और इससे प्रति वर्ष 7 करोड़ 88 लाख 40 हजार किग्रा कार्बन डायक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है।
- वर्ष 2022-23 में हर ग्राम पंचायत के चार वार्ड में इसके तहत काम होगा और शेष में 2023-24 में काम होने की आशा है।

परिचय

ग्रामीण विकास बिहार में ही नहीं, संपूर्ण भारत के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का तात्पर्य ग्रामवासियों के जीवन स्तर में, खास कर सुदूर क्षेत्रों में समग्रता में सुधार से है। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण आबादी को आर्थिक और सामाजिक, दोनो तरह से ऊपर उठाने की योजना से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास राज्य के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।

गत पांच वर्षों में राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का औसतन 10.1 प्रतिशत खर्च किया है जो संपूर्ण भारत के स्तर पर इसके 5.8 प्रतिशत हिस्से के दुने से भी अधिक है। कुल व्यय में ग्रामीण विकास पर व्यय का हिस्सा बिहार में आम तौर पर बढ़ता गया है जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर सामान्यतः घटता गया है। वर्ष 2021-22 में बिहार में ग्रामीण विकास पर व्यय 15.6 हजार करोड़ रु. था जो 2019-20 के 13.2 हजार करोड़ रु. से 18.6 प्रतिशत अधिक है।

बिहार और भारत में ग्रामीण विकास पर व्यय का प्रतिशत (2017-18 से 2021-22)

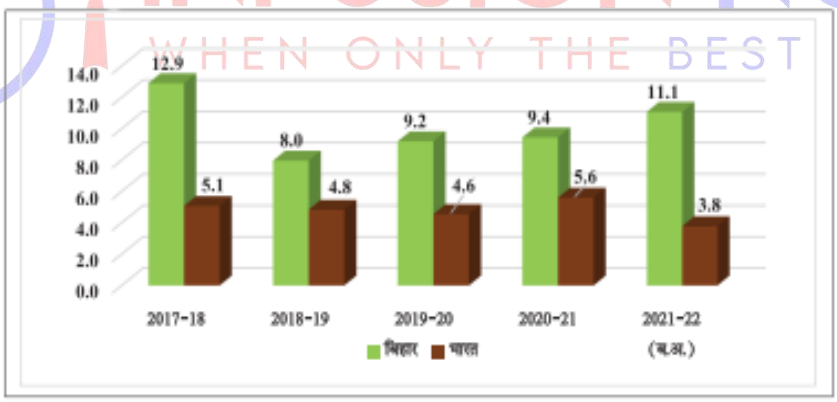

जीविका :- 'जीविका' के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (बीआरएलपीएस) ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में निबंधित संस्था है। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए थे जिनमें से 2.45 लाख समूहों का बैंकों के साथ ऋण-संपर्क है। अभी बैंक ऋण 5574 करोड़ रु. का है ।

वर्ष 2022-23 ने जीविका के रूपांतरण के नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया क्योंकि समिति ने विविधतापूर्ण आजीविका पर फोकस किया, मानव विकास के लिए व्यवहार परिवर्तन संवाद के विभिन्न मॉड्यूल सामने लाए और ग्रामीण गरीबों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का कनवर्जेंस किया।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)

FREE SAMPLE

RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/gubxrj

Online order - https://bit.ly/42AN5sZ

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO